

बाबूलाल ने पूछा, हफिजुल हसन के इस्तीफे की मांग करेंगे खड़गे?

● कहा, कांग्रेस व झामुमो गठबंधन की नींव परिवार-प्रेम का परिणाम है

नवीन मेल संवाददाता

रांची। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता



प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा। मरांडी ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस के 'राष्ट्रीय अध्यक्ष' मल्लिकार्जुन खड़गे जी संविधान बचाने की बात करने आ रहे हैं, तो क्या सबसे पहले आते ही वे सीएम सोरेन से हफिजुल हसन के इस्तीफे की मांग करेंगे? क्योंकि, ऐसे संविधान विरोधी व्यक्ति के साथ गठबंधन में बने रहना और उसी समय संविधान बचाओ रैली करना नैतिक रूप से सही नहीं है। बाबूलाल ने कहा कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि जैसे-जैसे नेशनल हेराल्ड केस की परतें खुलती जा रही हैं, कांग्रेस पार्टी की संविधान को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। कहा कि एक सोची-समझी साजिश के तहत जनता का ध्यान राहुल गांधी और सोनिया गांधी द्वारा किए गए घोटाले से भटकाने के

मरांडी ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का किया स्वागत

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को कैबिनेट में पूरे भारत में जातिगत जनगणना करवाने का निर्णय सराहनीय कदम है। कहा अब वोटबैंक की नहीं, वास्तविक सामाजिक न्याय की बात होगी। कहा दशकों से इस मुद्दे को कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने जातिगत जनगणना का इस्तेमाल केवल चुनावी हथियार की तरह करते आए हैं। अब जातिगत जनगणना समय की मांग बन चुकी है। समय आ गया है कि टुकड़ों में कटाई जा रही राज्य स्तरीय, असंगत और अपारदर्शी गणनाओं को छोड़ा जाए और पूरे देश के लिए एक समान, विश्वसनीय व तथ्य-आधारित जातिगत जनगणना को अपनाया जाए। कहा कि सही मायनों में सामाजिक न्याय की ओर कदम बढ़ाते हुए जातिगत जनगणना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए पीएम मोदी जी का आभार।

लिए यह सारा आडंबर रचा जा रहा है। नहीं तो, जिस पार्टी में खुद के नियम-कायदे केवल एक ही परिवार के सदस्य तय करते हों, वह पार्टी देश के संविधान की कितनी परवाह करेगी, यह जनता भली-भांति जानती है।

नरेश टिकैत जनता-किसानों से माफी मांगें : पवन साहू

नवीन मेल संवाददाता

रांची। भाजपा किसान मोर्चा (झारखंड) प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने नरेश टिकैत के पहलुगाम मामले पर देशद्रोही बयानबाजी की कड़े शब्दों में निंदा की है। पवन साहू ने कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 हिंदू तीर्थयात्रियों की निर्मम हत्या के बाद पूरा देश आक्रोशित है। देश की जनता एकजुट होकर पीएम मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कठोर निर्णय लेते हुए पाकिस्तान के साथ राजनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। पवन साहू ने कहा कि तथाकथित किसान नेता नरेश टिकैत की दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां



● कहा, नरेश टिकैत की टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं

ऐसे समय में आया, जब पूरा देश एकजुट है। कुछ तथाकथित किसान नेता राष्ट्र विरोधी बयान देकर देश के जख्मों पर नमक लिड़कने का कार्य कर रहे हैं। नरेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार को सिंधु जल संधि को रद्द नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 'भारत और पाकिस्तान

राज्य सरकार डीजीपी को रिटायर कराने पर असहमत

केंद्र सरकार को जवाब भेजने की तैयारी

नवीन मेल संवाददाता

रांची। राज्य सरकार ने डीजीपी



को 30 अप्रैल 2025 के दिन (बु ध वार) रिटायर कराने के निर्देश पर असहमति जताने की तैयारी में है। राज्य सरकार केंद्र को पत्र लिखेगी। इसकी तैयारी की जा रही है। केंद्र को भेजे जाने वाले जवाब में राज्य सरकार द्वारा डीजीपी की नियुक्ति के लिए बनाए गए नियम को सही बताया जाएगा। सुत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति प्रकरण में केंद्र द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के मुद्दे पर कानूनी राय लेने के बाद अपना जवाब भेजने की तैयारी की है। पत्र में केंद्र द्वारा उठाए गए हर बिंदु का जवाब भेजा जाएगा। राज्य सरकार का तर्क है कि डीजीपी

ब्यूरोक्रेसी में अलग-अलग तरह की चर्चा है

डीजीपी अनुराग गुप्ता के मुद्दे पर लगातार बुधवार को भी अतिश्रुति की स्थिति बनी रही। राज्य सरकार ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को पद से हटाने का कोई आदेश जारी नहीं किया जा ही उन्होंने पद त्याग किया। ब्यूरोक्रेसी में अलग-अलग तरह की चर्चा है। कुछ यह मान रहे हैं कि अनुराग गुप्ता केंद्र सरकार के निर्देश के विपरीत डीजीपी के पद पर बने हुए हैं। उन्हें डीजीपी के पद से हटाने के लिए सरकार की ओर से आदेश जारी करने की बाधता है या नहीं। इस मुद्दे पर भी अधिकारियों की अलग अलग राय है। कुछ अधिकारियों का मानना है कि केंद्र सरकार ने अनुराग गुप्ता को रिटायर कराने के आदेश दिया है। किसी अधिकारी के रिटायरमेंट के समय सरकार के स्तर से कोई आदेश नहीं निकला जाता है। रिटायरमेंट की तिथि पर संबंधित अधिकारी द्वारा अपना पद त्याग कर दिया जाता है। दूसरी तरफ कुछ अधिकारियों का यह मानना है कि सरकार ने अनुराग गुप्ता को दो साल के लिए डीजीपी के पद पर नियुक्त किया है। इसलिए केंद्र के निर्देश के आलोक में अनुराग गुप्ता को रिटायर कराने के लिए उन्हें डीजीपी के पद से हटाने का आदेश जारी करना जरूरी है।

नियुक्ति के लिए बनाया गया नियम सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप है।

सरकार का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में डीजीपी की नियुक्ति के लिए पैनल बना कर यूपीएससी से अनुमोदित कराने का निर्देश अस्थायी व्यवस्था के तहत दिया है। राज्य सरकार ने पुलिस

एक्ट में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए डीजीपी की नियुक्ति नियमावली बनाई है। सरकार द्वारा बनाया गया नियम सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुकूल है।

सरकार यह मानती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में डीजीपी का कार्यकाल दो साल का निर्धारित है। इसलिए इससे पहले राज्य के डीजीपी को पद से हटाना सुप्रीम कोर्ट

के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होगा।

सरकार की तरफ से यह भी तर्क है कि डीजीपी की नियुक्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला विचारार्थी है। न्यायालय द्वारा अभी यह फैसला किया जाना बाकी है कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति नियमानुसार है या नहीं। इसलिए इस मुद्दे पर न्यायालय के फैसले के पहले भी पद से हटाना सही नहीं है।

जातीय जनगणना का ज़ेएमएम ने किया स्वागत विपक्ष की मांग के आगे झुकी केंद्र सरकार : सुप्रियो

नवीन मेल संवाददाता

रांची। जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो



भट्टाचार्य ने कहा कि यह निर्णय केंद्र सरकार को पहले ही ले लेने थे। जेमएमए के अलावे और भी भाजपा की जो विरोधी पार्टियां बिहार हो, कर्नाटक या तेलंगाना हो, ने मांग रखी थी कि जातिगत जनगणना हो। उस समय पीएम और भाजपा के बड़े नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया था। मगर अब जन-दबाव के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। भारत सरकार के राजनीतिक

मामलों पर कैबिनेट समिति ने जनसंख्या की जनगणना में जातीय जनगणना को स्थान दिया है। भारत सरकार के इस निर्णय का झामुमो ने स्वागत किया है, उन्होंने कहा है कि यह हमारी नैतिक जीत है। वहीं श्री भट्टाचार्य ने कहा कि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि झारखंड राज्य के आदिवासियों को सरना धर्म कोड मिलेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या जनगणना के बाद ही जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि परिसीमन करना असान हो। 2025 में हमलोग महिला आरक्षण देने की बात कर रहे हैं ऐसे में परिसीमन से पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए।

न्यूज़ बॉक्स

आजसू ने नाइजर में फंसे पांच श्रमिकों की रिहाई की मांग की

रांची। अफ्रीकी देश नाइजर में तंकरादियों के शिकार झारखंड के गिरिडीह जिले के



बगोदर क्षेत्र के पांच श्रमिकों की रिहाई को लेकर आजसू पार्टी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। आजसू पार्टी के नेता संजय मेहता ने बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और नाइजर में भारत के राजदूत सीताराम मोना को पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। ज्ञात हो कि विगत 25 अप्रैल को नाइजर की राजधानी नियामे से लगभग 115 किलोमीटर दूर तिल्लाबेरी में आतंकवादियों ने एक पावर ट्रांसमिशन साइट पर हमला किया। इस हमले के बाद 12 सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई और बगोदर के पांच मजदूरों संजय महतो, चंद्रिका महतो, फलजीत महतो, रानू कुमार और उत्तम महतो का अपहरण कर लिया गया। ये मजदूर कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (केपीआईएल) के प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। संजय मेहता ने पत्र में सभी मजदूरों के पासपोर्ट विवरण और संपर्क जानकारी भी मंत्रालय को दी है। साथ ही, उनके परिजनों की चिंता और व्यथा को रेखांकित किया है। उन्होंने विदेश मंत्री और भारत के राजदूत से इस गंभीर मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर मजदूरों की संकुशल वतन वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। संजय मेहता ने बताया की नाइजर में भारत के एंबेसडर सीता राम मोना को सूचित करने के बाद उनके कार्यालय ने हमें सूचित किया है कि भारतीय दूतवास ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को, डालसा जुटी तैयारी में

रांची। झालसा के निदेश पर वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को होना सुनिश्चित हुआ है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए समझौतापूर्व बैठक 10 मार्च से शुरू हो चुका है। इसी के मद्देनजर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के द्वारा भी तैयारी शुरू कर दिया गया है। सभी न्यायालयों से वादकारियों को नोटिस भेजने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के कार्यरत सभी पीएलवी को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जोर-शोर से प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के पश्चात ग्रामोणों व जरूरतमंदों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दें, ताकी लोग जागरूक हो, वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा उठा सके और अपने वादों का निस्तारण निशुल्क करा सकें। ज्ञात हो कि 10 मई को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों का निस्तारण मध्यस्थों व अधिवक्ताओं के माध्यम से किया जायेगा।

जातीय गणना कराना ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम : राजेंद्र प्रसाद

रांची। मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने केंद्र सरकार की ओर से जातीय जनगणना कराने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी के सच्चे हितैषी हैं। प्रसाद ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। राजेंद्र प्रसाद ने जातीय जनगणना कराने के निर्णय को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया है। कहा कि जातीय जनगणना की मांग लंबे समय से होते रही है। राजेंद्र प्रसाद ने यह भी कहा कि जातीय जनगणना नहीं होने से देश में पिछड़ी जातियों के आंकड़े को लेकर देश में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। प्रसाद ने कहा कि जातीय जनगणना से ओबीसी की आबादी के अनुसार हिस्सेदारी तय होगी।



मुख्यमंत्री झारखण्ड अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना

झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना

श्रमिक औजार सहायता योजना

मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना

चिकित्सा सहायता योजना

मातृत्व प्रसुविधा योजना

अनाथ पेंशन योजना

मुख्यमंत्री झारखण्ड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष

निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना

विवाह सहायता योजना

पारिवारिक पेंशन योजना

अंत्येष्टि सहायता योजना

निःशक्ता पेंशन

पेंशन योजना

श्रमिकों को मिल रहा हक-अधिकार साथ है हेमन्त सरकार

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुभकामनाएँ और जोहार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

PR No. 3514899 (Labour Employment and Training) 2025-26

अक्षय तृतीया पर दिगंबर जैन मंदिरों में गन्ने का रस किया गया वितरित

मंदिरों में दिनभर भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना रहा

नवीन मेल संवाददाता। हजारीबाग अक्षय तृतीया (अखा तीज) के पावन अवसर पर मंगलवार को हजारीबाग नगर क्षेत्र के दोनों प्रमुख दिगंबर जैन मंदिर – बड़ा बाजार और बौंडम बाजार – में प्रातः काल से ही धार्मिक वातावरण श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण रहा। श्रद्धालुओं ने शांतिधारा, अभिषेक एवं विशेष पूजा-अर्चना कर प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव (आदिनाथ) के प्रथम आहार दान दिवस को श्रद्धापूर्वक मनाया। जैन परंपरा के अनुसार, भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा लेने के पश्चात छह माह तक उपवास किया और फिर नियमपूर्वक आहार की प्रतीक्षा करते हुए नगर-नगर विचरण करते रहे। वे केवल शुद्ध भावना से और



विधिपूर्वक दिए गए आहार को ही स्वीकार करने के लिए तत्पर थे। अंततः तेरहवें मास के अंत में, अक्षय तृतीया के दिन, हस्तिनापुर के राजा सुमित्र के पुत्र श्रेयांस कुमार को अपने पूर्व जन्म की स्मृति जाग्रत हुई, जिसके प्रभाव से उन्हें यह ज्ञान हुआ कि मुनिराज

को किस विधि से आहार दिया जाता है। उन्होंने नियमपूर्वक गन्ने का रस (इक्षुरस) अर्पित किया, जिसे भगवान ऋषभदेव ने स्वीकार किया। यही ऐतिहासिक घटना जैन इतिहास में प्रथम आहार दान के रूप में प्रसिद्ध हुई, जिसे आज आहार दान दिवस के रूप में मनाया

जाता है। आज इस परंपरा को जीवंत करते हुए, हजारीबाग के दोनों मंदिरों में गन्ने का रस भक्तों के बीच वितरित किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस रस का पान कर भगवान ऋषभदेव के प्रथम आहार ग्रहण की स्मृति को आत्मसात किया। मंदिरों में दिनभर

भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना रहा। इस अवसर पर मौडिया प्रभारी श्री राजेश लुहाड़िया ने बताया कि अक्षय तृतीया केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जैन संस्कृति के जीवंत मूल्यों – त्याग, तप, दान, संयम और सेवा – की प्रेरक स्मृति है। यही वह ऐतिहासिक दिन है जब जैन धर्म में दान तीर्थ की परंपरा का प्रवर्तन हुआ। प्रथम आहार दान की यह घटना हमें यह सिखाती है कि शुद्ध भाव से दिया गया आहार न केवल मुनिराज के लिए बल्कि दाता के लिए भी आत्मकल्याण का माध्यम बनता है। इसी कारण आज के दिन कुछ न कुछ दान देने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जो पुण्य, परोपकार और आत्मशुद्धि का प्रतीक है।

राखा कॉपर माईस चालू करने से पूर्व कर्मियों का बकाया दें : सनातन भक्त

जादूगोड़ा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स (वर्ल्ड) द्वारा राखा कॉपर माईस यूनिट को दोबारा शुरू करने की तैयारी की जा रही है. इसको लेकर अगले महिने जनसुनवाई होना है. इसके पहले भूतपूर्व कर्मचारियों ने कंपनी से अपने बकाया भुगतान की मांग की है. भूतपूर्व कर्मचारियों का कहना है कि हर कर्मचारी का लगभग तीन लाख रुपये बकाया है, जिसे कंपनी को जल्द से जल्द भुगतान करना चाहिए. इस मुद्दे को लेकर 4 मई को राखा कॉपर दुर्गा पूजा मैदान में एक बैठक बुलाई गयी है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जायेगी. भूतपूर्व कर्मचारियों के नेता सनातन भक्त ने कहा कि वे माईस खुलने का स्वागत करते हैं, लेकिन पुराने कर्मचारियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने यह भी मांग की कि माईस में नई नियुक्तियों में भूतपूर्व कर्मचारियों के बेटे-बेटियों या नोमनी को प्राथमिकता दी जाये, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और क्षेत्र में बेरोजगारी कम हो.



जादूगोड़ा में मनी पूर्व विधायक सनातन मांझी की पुण्य तिथि



जादूगोड़ा। जादूगोड़ा से सटे बालीजुडी में पोटका के पूर्व विधायक और झारखंड आंदोलनकारी सनातन मांझी की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई. लोगों ने बालीजुडी चौक स्थित सनातन मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी. समारोह को संबोधित करते हुए सुशील हांसदा ने कहा कि शिक्षा व सामाजिक क्षेत्र में स्वर्गीय सनातन मांझी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता. सरल व मृदुभाषी स्वभाव की वजह से वह सभी के चहेते थे. मेडिकल कैंप में 130 मरीजों का इलाज, बांटी गयी दवाईयां

आनंद कुशल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से लगाया गया कैंप



जादूगोड़ा। आनंद कुशल चैरिटेबल ट्रस्ट जमशेदपुर की ओर से आदिवासी बालिका उच्च विद्यालय गोपालपुर में आज मेडिकल कैंप लगाया गया. इस कैंप में 130 ग्रामीणों समेत स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर मुफ्त में दवा बांटी गयी. कार्यक्रम को सफल बनाने में आनंद कुशल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बादल चंद्र भक्त, चित्तरंजन भक्त, डॉक्टर अजीत राय, डॉक्टर नंदिता नागर, विनय कुमार ठाकुर (प्रबंधन) और भूदेव भक्त ने अहम योगदान दिया. इस बाबत ट्रस्ट के सदस्य विनय कुमार ठाकुर ने कहा कि यह संस्था उपयोगी शिक्षा और ट्राइबल आर्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी काम कर रही है. इसका उद्देश्य है कि पैसे की कमी के कारण कोई भी प्रतिभा दब न जाये. संस्था ऐसे बच्चों की पहचान कर रही है, जिन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत है, ताकि उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिल सके.

घर पर काम कर रहे मजदूरों के साथ बाबूलाल ने बैठकर लगाया खपड़ा, कहा

आप कहीं भी पहुंच जाएं, अपने संघर्ष को कभी नहीं भुलाएं

नवीन मेल संवाददाता। तिसरी कभी खेतों में हल चलाते तो कभी पैदल ही कई किलोमीटर का सफर तय करते, कभी कुदाल लेकर काम करते तो कभी घर की छप्पर पर खपड़ा लगाते। जी हां, सुबे के पहले मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, कई दफा सांसद और विधायक रहे साथ ही वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन बाबूलाल मरांडी अपनी शालीनता के लिए जाने जाते हैं। इतने बड़े-बड़े पदों पर रहने के बावजूद कई दफा उन्हें खेतों में काम करते तो कभी हल चलाते देखा गया है। एक बार फिर बाबूलाल को कुछ ऐसा ही करते देखा गया है। दरअसल बाबूलाल मरांडी अपने पैतृक आवास कोइदांबाक आए हुए थे। जहां उनके घर की छप्पर पर खपड़ा



लगाने का कार्य चल रहा था। संघर्षों से निकले व मिट्टी से जुड़े बाबूलाल भला इसे देख कैसे खुद को रोक पाते। वे स्वयं ही लकड़ी की सीढ़ियों से होते हुए घर की छप्पर पर चढ़ गए और काम कर रहे लोगों के साथ बैठकर खपड़ा लगाने लगे। इस दौरान उनके कुछ शुभचिंतकों ने कड़ी धुप को देखते हुए उससे नीचे उतर जाने का

आग्रह भी किया लेकिन बाबूलाल तो ठहरे किसान आदमी. वे भला इतनी जल्दी कैसे उतर जाते। उन्होंने थोड़ी देर तक खपड़ा फेरा फिर वहां से उतरे। बाबूलाल का मानना है कि व्यक्ति को हमेशा मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए, भले ही आप कहीं भी पहुंच जाएं लेकिन अपने संघर्ष अपनी शालीनता को कभी नहीं भूलनी चाहिए।

बीआरसी भवन में स्कूल रुआर कार्यशाला कार्यक्रम आयोजित

बच्चों को स्कूल से जोड़ना मुख्य उद्देश्य : बीडीओ



नवीन मेल संवाददाता। बेंगाबाद बेंगाबाद बीडीओ सुनील कुमार मुर्मू ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल रूआर कार्यक्रम की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत बच्चों को स्कूल से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है। बेंगाबाद के बीआरसी कार्यालय के सभागार में स्कूल रूआर कार्यक्रम के तहत बुधवार आयोजित एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय कार्यशाला में बीडीओ ने अपने संबोधन में उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि किसी कारण वश विधालय से बच्चे छिजित हैं, उन्हें स्कूल से जोड़ने और विधालय में उसके ठहराव के लिए आवश्यक प्रतिनिधियों एवं शिक्षकों को प्रेरित किया गया है।

के लिए आंगनबाडी सेविका से बच्चों की सूची लेना है। ताकि आंगनबाडी सेंटर के बाद बच्चे स्कूल से जुड़ सकें और कोई नामांकन से छूट नहीं सके। इसके आलावे स्कूल में बच्चों को मिलने वाली एमडीएम के तहत पौष्टिक

ड्रॉप आउट शिक्षा का सबसे बड़ा बाधक

सीओ प्रियंका प्रियदर्शी ने कहा कि ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ना जरूरी है। ताकि उसकी शिक्षा पूरी हो सके। स्कूल से दूर रहने वाले बच्चों की शिक्षा अपूर्ण रह जाती है लेकिन स्कूल रूआर कार्यक्रम के तहत ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़कर आंगनबाडी से लेकर बारहवीं तक की शिक्षा पूर्ण करना है। मौके पर बीस सूत्री के प्रखंड अध्यक्ष नुनुराम किशु टाडगन ने कहा कि नारीबां के उच्चाय के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल रूआर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। शत प्रतिशत ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए इसे अभियान के रूप में लेना होगा। बीडीओ सुनील कुमार मुर्मू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता किया। मौके पर प्रमुख मीना देवी, सीओ प्रियंका प्रियदर्शी, बीस सूत्री प्रखंड अध्यक्ष नुनुराम किशु टाडगन, बीडीओ स्वाज कुमार मंडल, बीपीओ के डी सिंह, वाईन सुनिता सिंह, कुमारी पुनम, बीआरपी निशा कुमारी, आशीष सुनम, बंजनाथ प्रसाद यादव, तालजोत प्रसाद यादव, ओ हनीफ अंसारी, लेखा पाल संजय कुमार यादव, शाहिद अंजुम, रामदेव प्रसाद वर्मा सहित कई अन्य शिक्षक उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि पांच से लेकर छह वर्ष के बच्चों को स्कूल से जोड़ने

आहार और विधालय के रंग रोमन पर भी चर्चा की गई।

गिरिराज सेना के शिविर में 165 यूनिट रक्त संग्रह

चक्रधरपुर। गिरिराज सेना के संस्थापक दिवंगत कमलदेव गिरि के जन्मदिन पर बुधवार को 14वां रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ. चक्रधरपुर की श्याम नारायण शौंडिक धर्मशाला में आयोजित शिविर का उद्घाटन अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अंशुमान शर्मा, शिक्षक श्रीकांत मजुमदार व भाजपा नेता तीर्थ जमुदा ने स्व. कमलदेव गिरि की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर किया. शिविर में शाम पांच बजे तक 188 लोगों ने रक्तदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि कुल 165 यूनिट रक्त संग्रह किया गया. 12 महिलाओं ने भी रक्तदान किया. पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व विधायक शशिभूषण सामंड, गीता कोड़ा, भाजपा के जिला मंत्री सुरेश साव,टाइगर क्लब जमशेदपुर के अध्यक्ष आजाद गिरि, भाजपा विधायक सरयू राय के प्रतिनिधि धर्मेन्द्र प्रसाद रक्तदाताओं का हासला बढ़ाया. मधु कोड़ा ने कहा कि युवा नेता कमल देव गिरि भले ही हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन समाज के लिए उन्होंने जो सपना देखा था उसे गिरिराज सेना परिवार सेना की ओर से सभी रक्तदाताओं को अंग वस्त्र, मोमेटो व स्मृति पत्र देकर सम्मानित किया गया. इस अवसर पर कमलदेव गिरि के बड़े भाई उमाशंकर गिरि, फुलनदेव गिरि, बहन पूजा गिरि, मनोज जितंद, धीरज ठाकुर रिक्की खबड़ा, सतीश अग्रवाल आदि मौजूद थे.

नीट परीक्षा 4 को, डीसी व एसएसपी ने परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा



नवीन मेल संवाददाता। धनबाद देश के मेडिकल कॉलेजों नामांकन के लिए नीट परीक्षा 4 मई को होगी. परीक्षा को लेकर धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. परीक्षार्थियों को शांतिपूर्ण और पारदर्शी माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डीसी माधवी मिश्रा व एसएसपी एचपी जनादनन ने बुधवार को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया. उन्होंने केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, पानी, बिजली व शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करें. एनटीए की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करने का भी निर्देश दिया. अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा

दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी. सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे. प्रवेश के समय पुरुष और महिला परीक्षार्थियों को सघन जांच की जाएगी. केंद्रों पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है. साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी. निरीक्षण के दौरान सिटी एसपी अजित कुमार, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीपूष सिन्हा, एसडीएम राजेश कुमार, एनटीए सिटी कोऑर्डिनेटर शैलेन्द्र शर्मा और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह मौजूद थे.

रांची, गुरुवार, 01 मई 2025

न्यूज बॉक्स

पूर्व कर्नल ने पीएम से मांगी सेना में दोबारा बहाली की अनुमति

धनबाद। पहलगाम आतंकी हमले ने देशभर में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है. धनबाद निवासी सेना से रिटायर्ड कर्नल जेके सिंह भी इस हमले से मर्माहत हैं. उन्होंने पएम मोदी को पत्र लिखकर एक बार फिर सेना में बहाल किए जाने की अनुमति मांगी है. कर्नल जेके सिंह सेना की कैवेलरी यूनिट से रिटायर्ड अधिकारी हैं. उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 31 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा की है, जिनमें से 14 वर्ष जम्मू-कश्मीर में बिताए हैं. इस दौरान वे उत्तर कश्मीर में पैरा कमांडो के रूप में और बाद में दक्षिण कश्मीर के संवेदनशील इलाकों अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पहलगाम में आतंकवाद विरोधी अभियानों का नेतृत्व करते रहे. वहीं पहनते समय उन्होंने देश के लिए जीने-मरने की कसम खाई थी और आज भी उनका यह प्रण उनके हृदय में ज्यों का त्यों जीवित है. पहलगाम में हुए कायरा आतंकी हमले ने उन्हें झकझोर दिया है और वह एक बार फिर मातृभूमि की रक्षा के लिए सेना में शामिल होने को तैयार हैं.



माओवादी एरिया कमांडर सलूका के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार



चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने माओवादी एरिया कमांडर सालूका कायम की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर दिया है.पुलिस की टीम जिले के बंदगांव क्षेत्र स्थित सलूका कायम के घर में छापेमारी की. लेकिन वह फरार था. इसके बाद पुलिस की टीम ने ढोल-नगाड़े के साथ पहुंची और उसके घर के बाहर इश्तेहार चिपकाया. माओवादी एरिया कमांडर ने सालूका कायम के खिलाफ जिले के कराईकेला थाना में 04/23 के तहत प्राथमिकी दर्ज है. दोनों मामलों में वह

प्राथमिक अभियुक्त है. मिली जानकारी के अनुसार, कराईकेला थाना की पुलिस सोनुवा थाना क्षेत्र के कुदाबुरु गांव स्थित सालूका कायम के घर में छापेमारी की. लेकिन वह फरार था. इसके बाद पुलिस की टीम ने ढोल-नगाड़ा बजाते हुए उसके घर के बाहर इश्तेहार चिपकाया. कराईकेला थाना प्रभारी अंकित कुमार ने माओवादी सालूका के परिवार वालों से बातचीत भी की. साथ ही सालूका को जल्द आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी.

संस्कृति की रक्षा के लिए युवा पीढ़ी को जागरूक करें :जगत मांझी



चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर स्थित सद बमड़ी में बुधवार को झंडा पुनर्स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया. कुडुख सरना पड़हा समिति के तत्वावधान में हुए इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि मनोहरपुर विधायक जगत मांझी शरीक हुए. विधायक ने पूजा स्थल में पूजा-अर्चना कर और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की. विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए युवा पीढ़ी को जागरूक करें. सामाजिक विकास के लिए एकजुटता जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि क्षेत्र से बहुत सारे लोग रोजगार के सिलसिले में दूसरे प्रदेश में पलायन कर जाते हैं. लेकिन जब वापस लौटते हैं तो अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और सभ्यता को भूल जाते हैं. उन्होंने समाज के बुद्धिजीवियों से आग्रह किया कि भाषा-संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए युवा पीढ़ी को जागरूक करने का काम करें. बच्चों के शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की अपील की. कहा कि शिक्षा के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता है. कार्यक्रम में कलाकारों ने भजन व जतरा गीत प्रस्तुत किये. सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को विधायक व अन्य अतिथियों ने पुरस्कृत किया. मौके पर कुडुख सरना जागरण मंच के अध्यक्ष रबी लकड़ा, बुधेश्वर धनवार, सुनील तिकी, कैलाश कुजूर, धर्मेन्द्र बरूवा, जगरा तिकी, मंगल सिंह एक्का, इदन उरांव, मनीष उरांव, अजय कच्छप, संजीव गंताइत, राजू सिंह आदि उपस्थित थे.

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(जिला खेल शाखा)

दूरभाष : Email ID : ramgarh-sports@jharkhandmail.gov.in dsoramgarh48@gmail.com

प्रेस-विज्ञापि

रामगढ़ जिला अन्तर्गत खिलाड़ियों को CSR मद से खेल सामग्री /खेल कीट /अन्य सुविधाएं दी जाने की योजना है।

रामगढ़ जिला के सभी खिलाड़ियों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय /भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त खेलों में विगत पाँच वर्ष (2021 से 2025) में अन्तर्राष्ट्रीय /राष्ट्रीय स्तर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिये हो एवं वर्तमान मे खेल रहे है। वैसे सभी खिलाड़ी अपनी सम्पूर्ण विवरणी (यथा-आवेदन पत्र https://ramgarh.nic.in पर उपलब्ध हैं, सर्टिफिकेट, आधार /आवासीय प्रमाण पत्र आदि) को जिला खेल कार्यालय, समाहरणालय, भवन A- Block, द्वितीय तल कमरा संभ- 303 छतरगण्डू, रामगढ़ अथवा Email ID : ramgarh-sports@jharkhandmail.gov.in, dsoramgarh48@gmail.com पर उपलब्ध करायेंगे। ताकि खिलाड़ियों को जिला प्रशासन, रामगढ़ के द्वारा CSR मद से खेल सामग्री /खेल कीट /अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकें। अधिक जानकारी हेतु श्री विकास कुमार गोप, जिला खेल समन्वयक के मोबाईल नं०-7484914066 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ह०/-

जिला खेल पदाधिकारी,रामगढ़।

PR 351479 District(25-26)JD



एचईसी कभी गौरव था आज है खस्ताहाल

देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थापित कंपनी में है कार्यशील पूंजी की कमी

रांची में हटिया के पास स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी) भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। यह भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन है। एचईसी में कास्टिंग और फोर्जिंग, फोर्जिंग, फैब्रिकेशन, असेंबली, परीक्षण आदि समस्त सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। इसे इस्पात, खनन, रेलवे, एयरोस्पेस, रक्षा, बिजली आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमता को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्थापित किया गया था, जिससे कि देश को भारी उपकरणों के लिए आयात की निर्भरता कम किया जा सके। इस कंपनी की स्थापना देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया था। यह झारखंड का गौरव था। लेकिन, अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए लॉच पैड तथा उपस्कर बनाने वाली कंपनी आज खस्ताहाल है। एचईसी ने भारतीय इस्पात उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने देश की कई प्रमुख परियोजनाओं में भी योगदान दिया है। इस्पात संयंत्रों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के मशीनरी और उपकरणों का निर्माण कर देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। लेकिन, खुद ही

सुरिकल में फंस गया है। कई वर्षों से एचईसी को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब तो यह हाल है कि इसके कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवार के जीवन यापन में समस्या आ रही है। उनके बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। कंपनी को पर्याप्त कार्यशील पूंजी नहीं मिल पाने के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। आर्थिक संकट के कारण कच्चा माल खरीदने और उत्पादन जारी रखने में दिक्कत हो रही है। कुछ प्लांट्स कच्चे माल की कमी के कारण बंद हो गए हैं। एचईसी में कुछ जरूरी राँ मटेरियल की भी भारी कमी हो गई है। इससे उत्पादन और बिक्री दोनों प्रभावित हैं। साथ ही, पुरानी मशीनें बार-बार खराब हो जा रही हैं। कंपनी को ऑर्डर समय पर नहीं मिल पा रहा है। नए कार्यादेश नहीं मिल पा रहे हैं। नए कार्यादेश नहीं मिलने से कंपनी की स्थिति और खराब होते जा रही है। खराब आर्थिक स्थिति के कारण एचईसी को निजीकरण की आशंका से भी जुझना पड़ रहा है। इससे कर्मचारियों में भी अनिश्चितता बनी हुई है। एचईसी की खराब आर्थिक स्थिति के लिए कुछ हद तक प्रबंधन की उदासीनता भी जिम्मेदार है।

एचईसी के प्रमुख उत्पाद

- स्टील सेक्टर के उपकरण
- खनन सेक्टर के उपकरण
- क्रशिंग उपस्कर
- खनिज प्रोसेसिंग उपकरण
- क्रेन निर्माण, मशीन टूल
- कास्टिंग और फोर्जिंग

एचईसी की ईकाई

- भारी मशीन उत्पादन संयंत्र
- फाउंड्री फोर्ज संयंत्र
- भारी मशीन टूल्स संयंत्र
- परियोजना विभाग

विशेष योग्यताएं

- अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए लॉच पैड तथा उपस्कर निर्माण
- थोक सामग्री प्रबंधन की र्कनी परियोजनाओं का क्रियान्वयन
- नीतिगत उपयोग/प्रयोग के लिए विशेष स्टील का विकास



एचईसी में आर्थिक संकट के कारण

- कार्यशील पूंजी की कमी
- नए कार्यादेश का अभाव
- ग्राहकों की मांग ससनय पर पूरा नहीं होने से आर्डर समय पर नहीं मिलना
- निजी करण की आशंका से कर्मियों में उदासीनता
- पुराने उपकरणों का बार-बार खराब होना
- कुछ प्लांट में राँ मटेरियल की कमी



श्रम के सम्मान का उत्सव है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस

‘अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस’ श्रम के सम्मान का एक बड़ा उत्सव है। समाज, देश, यहां तक कि मानवता की प्रगति भी उनलोगों पर टिकी हुई है, जो अपने काम को समर्पित भाव से करते हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि किसी देश का विकास उसके किसान और कारगरों पर निर्भर करता है। वास्तव में किसी भी समाज, देश, उद्योग की रक्की में ज्ञान और श्रम दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी उद्योग की सफलता बेहतर योजना और समझदार व कुशल श्रमिक के बिना संभव नहीं है।

वर्ष 1889 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस का आयोजन हुआ, जिसमें आठ घंटे के कार्य दिवस के लिए मजदूर वर्ग की मांगों के समर्थन में एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए एक प्रस्ताव अपनाया गया। श्रमिकों और समाजवादियों के इस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में घोषित किया। दुनिया भर के अधिसंख्य देश 1 मई को ही श्रमिक दिवस मनाते हैं। वहीं, अमेरिका और कनाडा सितंबर के पहले सोमवार को अपना मजदूर दिवस मनाते हैं।

दूसरी ओर, 1 मई की तारीख को अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर ने अमेरिका में एक आम हड़ताल की याद में चुना था, जो शिकागो में 1 मई 1886 को शुरू हुई थी और चार दिन बाद ‘हे मार्केट’ घटना के साथ समाप्त हुई थी। आज अगर कर्मचारियों के लिए दिन में काम के 8 घंटे तय हैं, तो वह शिकागो की आंदोलन की ही देन है। श्रमिक आंदोलन और मई दिवस को समझने के लिए तीन प्रमुख जगहों के आंदोलन पर ध्यान देना होगा - 1. अमेरिका, 2. यूरोप और 3. यूएसएसआर (अब रूस)। 19वीं शताब्दी में अमेरिका के ऐतिहासिक श्रमिक संघ आंदोलन के कारण श्रमिक दिवस को मान्यता मिली। वर्ष 1889 में समाजवादी समूहों और ट्रेड यूनियनों के एक अंतरराष्ट्रीय महासंघ ने शिकागो में हुई हे मार्केट घटना (1886) को याद करते हुए श्रमिकों के समर्थन में 1 मई को ‘मई दिवस’ के रूप में मान्यता दिया था। दूसरी ओर, जुलाई 1889 में यूरोप में पहली ‘इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज’ द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह प्लान किया गया कि 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस (मई दिवस) के रूप मनाया जाएगा। इसके बाद 1 मई, 1890 को पहला मई दिवस मनाया गया था। वहीं, वर्ष 1917 में हुई रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ (यूएसएसआर) और पूर्वी ब्लॉक राष्ट्रों ने मजदूर दिवस मनाना शुरू किया। वास्तव में, मार्क्सवाद और समाजवाद जैसी नई विचारधाराओं ने श्रमिकों से संबंधित मुद्दों की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया था। सभी लोगों ने श्रम के मूल्य को समझा और उसका सम्मान किया।

‘हे मार्केट’ घटना का पड़ा वैश्विक प्रभाव

संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो के ‘हे मार्केट’ में कपड़ा श्रमिकों ने हड़ताल 1 मई 1886 को आठ घंटे काम करने को लेकर जो आंदोलन किया था, उसका वैश्विक प्रभाव पड़ा। यह आंदोलन कई देशों में आठ घंटे का कार्य दिवस तय करने में सफल रहा। वैसे, सबसे पहले 21 अप्रैल 1886 को ऑस्ट्रेलिया चिकटोरिया में आठ घंटे के कार्यदिवस को लेकर आंदोलन हुआ था। इसी आंदोलन से प्रभावित होकर शिकागो के हे मार्केट के श्रमिकों ने भी वर्क डाउन या स्ट्राइक किया। शिकागो शहर में हे मार्केट घटना श्रमिकों के समर्थन में एक शांतिपूर्ण रैली थी।

भारत में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान

भारत में देश के 50 करोड़ से अधिक संघटित और असंघटित श्रमिकों के कल्याण के लिए तीन श्रम संहिता विधेयक पारित किए गए हैं। इन तीन कानूनों के माध्यम से श्रमिकों को हर तरह से सुरक्षा देने की कोशिश की गई है।

ये तीन श्रम संहिता निम्न हैं :

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

वर्ष 1923 में पहली बार भारत में मनाया गया था ‘श्रमिक दिवस’

भारत में वर्ष 1923 में ‘श्रमिक दिवस’ या ‘मई दिवस’ मनाया गया था। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई, 1923 को चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) में ‘मजदूर दिवस’ या ‘मई दिवस’ मनाया था। कम्युनिस्ट नेता मलयपुरम सिंगारवलु चेट्टियार ने श्रमिकों के लिए लाल झंडा उठाया था। यह पहली बार था कि किसी ने देश में लाल झंडा उठाया था। 1 मई, 1923 को मरीना बीच पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। साथ ही, एक संकल्प पारित कर यह सहमति बनाई गई कि इस दिवस को भारत में भी मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाए और इस दिन बुट्टी की घोषणा की जाए।

महात्मा गांधी और श्रमिक आंदोलन

अहमदाबाद की सूती मिल के श्रमिकों ने वर्ष 1918 में अपने अधिकारों और बेहतर काम की स्थिति के लिए आंदोलन किया था। यह सत्याग्रह था और महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। यह आंदोलन, गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। श्रमिक 50 प्रतिशत वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, लेकिन मिल मालिक केवल 20 प्रतिशत वृद्धि करना चाहते थे। गांधीजी ने श्रमिकों का समर्थन करने के लिए भूख हड़ताल भी की थी।

भारत में श्रम अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान में देश के श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान हैं। संविधान में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। ये सुरक्षा व्यवस्था मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में हैं।

ये सुरक्षा व्यवस्था निम्न हैं

- अनुच्छेद 14 :** इसमें विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राजक्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है।
- अनुच्छेद 19(1)(ग) :** नागरिकों को संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 21 :** प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 23 :** मानव के दुर्व्यापार और जबरदस्ती श्रम का प्रतिषेध करता है।
- अनुच्छेद 24 :** इसमें फैक्ट्री आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। यह अनुच्छेद चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों के किसी कारखाने, खान या किसी अन्य औद्योगिक व्यवसाय में कार्य करने पर रोक लगाता है।
- अनुच्छेद 39 (क) :** राज्य अपने नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 41 :** यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी एवं निःशक्ता तथा अन्य प्रकार के अभाव की स्थिति में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा।
- अनुच्छेद 42 :** यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।
- अनुच्छेद 43 :** यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि, उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभाग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। साथ ही, विशिष्टताय ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक और सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 43 (क) :** यह अनुच्छेद राज्य को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का अधिकार प्रदान करता है।

